

WE WISH YOU A
2026
HAPPY NEW YEAR

जालंधर ब्रीज

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	19°	7°
शनिवार	18°	6°
रविवार	19°	7°
सोमवार	19°	7°
मंगलवार	19°	7°
बुधवार	19°	7°
गुरुवार	19°	6°

*अंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com

JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 26 DECEMBER TO 01 JANUARY 2026 • VOLUME 23 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

1.1 करोड़ के इनामी टॉप कमांडर गणेश समेत 6 माओवादी ढेर

भुवनेश्वर. ओडिशा के कंधमाल जिले में चलाए गए एक बड़े माओवादी विरोधी अभियान में दो दिवसीय तलाशी अभियान के दौरान छह माओवादी मारे गए हैं। बुधवार को बेलघर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुम्मा वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। गुरुवार को चाकापद पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नारिंग झोला वन क्षेत्र में हुई एक अन्य मुठभेड़ में तीन और माओवादी मारे गए। विशेष खुफिया शाखा (एसआईडब्ल्यू) से मिली विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों ने कंधमाल के चाकापद पुलिस थाना क्षेत्र और राम्भा वन क्षेत्र में गंजाम जिले के आसपास के इलाकों में 23 टीमों, 20 विशेष अभियान समूह (एसओजी) टीमों, दो सीआरपीएफ टीमों और एक बीएसएफ टीम के साथ एक संयोजित अभियान चलाया। 25 दिसंबर की सुबह एसओजी टीमों की मौजूदगी में कई स्थानों पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुईं।

संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक टिकटों पर लागू होगा

नई दिल्ली. रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वृद्धि बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है। संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज मनाएगा राष्ट्रीय स्तर पर 'वीर बाल दिवस'

राष्ट्रपति प्रदान करेंगे 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' में किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

पुरस्कार के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों का चयन, पीएम मोदी भी उपस्थित रहेंगे

• जालंधर ब्रीज. नई दिल्ली

भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाएगा। इस अवसर पर भारत के युवा वीरों के साहस, बलिदान और अनुकरणीय मूल्यों को स्मरण किया जाएगा। इसी दिन विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भारत मंडप में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज दोपहर लगभग 12 बजकर

नक्सलवाद से मुक्ति की दहलीज पर खड़ा है ओडिशा : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि ओडिशा के कंधमाल जिले में एक बड़े अभियान में छह नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक्स पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम को उजागर करते हुए शाह ने कहा कि यह अभियान वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता है और ओडिशा को नक्सलवाद से पूर्ण रूप से मुक्त होने के करीब लाता है। शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओडिशा के कंधमाल में एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके सहित छह नक्सलियों को मार गिराया गया है। शाह ने आगे कहा कि इस सफलता के साथ, ओडिशा नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन को दहलीज पर खड़ा है।

पाई है। अधिकारियों ने बताया कि आगे तलाशी अभियान जारी है और अब माना जा रहा है कि देवूजी ही इस क्षेत्र में सक्रिय एकमात्र प्रमुख माओवादी नेता बचे हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाईबी खुराना की उपस्थिति में एक औपचारिक समारोह के दौरान आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण करने वाले जवानों ने एके-47 राइफल और सेल्फ-लोडिंग राइफलों (एसएलआर) सहित हथियारों का जखीरा जमा कराया और ओडिशा पुलिस नक्सल आत्मसमर्पण के बैनर तले उन्हें

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

ढाका. बांग्लादेश में भीड़ हिंसा की एक और घटना सामने आई है, जिसमें राजबारी जिले में बुधवार देर रात एक 29 वर्षीय हिंदू युवक को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि मुतक को पहचान मारु मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। उस पर रात करीब 11 बजे पांशा उपजिला के होसैडंगा पुराने बाजार में हमला किया गया और हमले के तुरंत बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए पांशा मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शेख मोइनुल इस्लाम ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने अमृत मंडल पर जबर्न वसूली का आरोप लगाया था जिसके बाद मामला भीड़ हिंसा में बदल गया। पुलिस ने बताया कि उनके रिकॉर्ड में अमृत मंडल को "सम्राट वाहिनी" नामक एक स्थानीय समूह के नेता के रूप में दर्ज किया गया था। वह होसैडंगा गांव के निवासी अक्षय मंडल का पुत्र था। पुलिस ने बताया कि हमले में शामिल लोगों की पहचान करने और हत्या की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद और अधिक अशांति को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के पर अपने संबोधन में कहा कि आज लखनऊ की धरती एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। उन्होंने देश और पूरी दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में भी लाखों ईसाई परिवार आज यह त्यौहार मना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रिसमस का यह उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए, यही हम सबकी सामूहिक कामना है।

मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 25 दिसंबर राष्ट्र के दो महान व्यक्तित्वों की जयंती का विशेष अवसर लेकर आता है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भारत की पहचान, एकता और गौरव की रक्षा के

लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन दोनों महान विभूतियों ने अपने विशाल योगदान से राष्ट्र निर्माण पर अमिट छाप छोड़ी है। मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि 25 दिसंबर महाराजा बिजली पासी जी की जयंती भी है। उन्होंने बताया कि लखनऊ का प्रसिद्ध स्थल पासी किला यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि महाराजा बिजली पासी ने वीरता, सुरासन और समावेशिता की ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे पासी समुदाय ने गर्व से आगे बढ़ाया है।

पांच रुपये की थाली वाली 'अटल कैंटीन' का शुभारंभ

नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 'अटल कैंटीन' योजना का भव्य आगाज किया है। इस योजना के तहत गरीबों और मजदूरों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पहली 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की। आज से 45 कैंटीन (आरके पुरम, जंगपुरा, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरला और बवाना आदि) में काम शुरू हो गया है। बाकी बची 55 कैंटीन भी आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरह चालू हो जाएंगी।

इन कैंटीनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कामकाजी मजदूरों को समय पर भोजन मिल सके। दोपहर का भोजन, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक और रात का भोजन शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मिलेगा। थाली में दाल, चावल, चपाती, एक मौसमी सब्जी और अचार परोसा जाएगा। योजना में भ्रष्टाचार रोकने और भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। खाना लेने के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम होगा।

डीजीपी ने गुरुद्वारा श्री फ़तेहगढ़ साहिब में माथा टेका, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायज़ा

3,400 से अधिक पुलिस कर्मी 24 घंटे तैनात; सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी सुनिश्चित

• जालंधर ब्रीज. श्री फ़तेहगढ़ साहिब छोटे साहिबज़ादों की अमर शहादत की स्मृति में फ़तेहगढ़ साहिब में आरंभ हो रही वार्षिक तीन दिवसीय शहीदी सभा के मद्देनज़र, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज गुरुद्वारा श्री फ़तेहगढ़ साहिब में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक समागम के सुचारु, शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई बहु-स्तरीय सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन योजना का व्यक्तिगत रूप से जायज़ा लिया। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादे बाबा ज़ोरावर सिंह जी और बाबा फ़तेह

सिंह जी की शहादत को समर्पित यह तीन दिवसीय वार्षिक शहीदी सभा आज से गुरुद्वारा श्री फ़तेहगढ़ साहिब में आरंभ हो गई है।

इस मौके पर डीजीपी पंजाब ने रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह और एसएसपी श्री फ़तेहगढ़ साहिब शुभम अग्रवाल के साथ सुरक्षा एवं प्रबंधन से जुड़े इंतज़ामों का जायज़ा लिया तथा मैदानी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पूरे क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से छह सेक्टरों में विभाजित किया गया है। पूरे समागम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छह एसपी रैंक के अधिकारियों और 24 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में 3,400 से अधिक पुलिस कर्मी 24 घंटे तैनात किए गए हैं।

सीएम मान ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जनवरी से शुरू करने की दी मंजूरी

3 करोड़ पंजाबियों को नए साल का तोहफा



• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़ पंजाब के निवासियों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग को जनवरी माह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद-रहित इलाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद-रहित इलाज मिलेगा।

सौरभ भारद्वाज समेत 'आप' नेताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला एक शिकायत के बाद दर्ज किया गया है जिसमें नेताओं पर कर्नाट प्लेस में सार्वजनिक रूप से किए गए एक राजनीतिक नाटक को दर्शाने वाले व्यंग्यात्मक वीडियो साझा करने का आरोप लगाया गया है। इस नाटक में सांता क्लॉस को मुछौटा पहने हुए, विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए और अंततः खराब वायुवत्ता के कारण बेहोश होते हुए दिखाया गया है।

शिकायत के अनुसार, 17 और 18 दिसंबर, 2025 को आप नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कर्नाट प्लेस में सार्वजनिक रूप से एक राजनीतिक नाटक का प्रदर्शन दिखाया गया है। इन वीडियो में दुनिया भर के ईसाइयों के लिए पूजनवी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक, सांता क्लॉस के रूप में सजे व्यक्तियों को अपमानजनक और उपहासपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। वीडियो में इन धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक संदेश देने के लिए केवल एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे सड़क पर "बेहोश" और "गिरते" हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में सांता क्लॉस को सड़क पर गिरते हुए और राजनीतिक संदेश देने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, वीडियो में सांता क्लॉस पर नकली सीपीआर करते हुए दिखाकर उनका उपहास किया गया है, जिससे संत निकोलस और क्रिसमस त्योहार की पवित्रता का अपमान हुआ है।

अगर अरावली नहीं रही तो उत्तर भारत में क्या बदल जाएगा? समझिए असली खतरे

Knowledge

जानिए आखिर क्या है मामला? साथ ही विस्तार से समझिए कि उत्तर भारत के लिए ये पहाड़ियां इतनी जरूरी कैसे हैं कि इनके न रहने से जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे?

• जालंधर बीज . फीचर

भारत में अरावली महज पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की सांस है। इन दिनों पर्यावरण कार्यकर्ता चेतावनी जारी कर रहे हैं कि 'इन सांसों पर गहरा संकट मंडरा' रहा है। इस सबकी शुरुआत हुई है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा सामने आने के बाद से। जानिए आखिर क्या है मामला? साथ ही विस्तार से समझिए कि उत्तर भारत के लिए ये पहाड़ियां इतनी जरूरी कैसे हैं कि इनके न रहने से जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे?

आखिर क्या है मामला?

सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल नई परिभाषा में कहा गया है कि उन्हीं भू-आकृति को अरावली श्रृंखला में शामिल किया जाएगा, जो जमीन से कम से कम 100 मीटर ऊंची होगी। जानकारों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा- ऐसा करने से करीब 90 फीसदी

पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर चली जाएंगी। इसके बाद यहां कोई रोक-टोक नहीं होगी, जिससे खनन, कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को क्षति पहुंचानी शुरू हो जाएगी।

उत्तर भारत की सांस, रोड़ और सुरक्षा कवच : अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये पहाड़ियां केवल 'सांस' ही नहीं 'सुरक्षा कवच' और 'रोड़' भी हैं, जाँपिए क्यों और कैसे?

दरअसल अरावली पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल, जल-जीवन का आधार और पर्यावरणीय संतुलन की रोड़ है। अगर अरावली नहीं रही, तो इसका असर सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अरबों जीव-जंतुओं, पौधों और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।



पांच बिंदुओं में समझिए अरावली की जरूरत : रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं। मानसून और बारिश के पैटर्न को भी निर्धारित और तय करने में रोल निभाती हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं : प्रदूषण और धूल को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। जैव विविधता की भरमार है यानी हजारों-लाखों तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। अगर पहाड़ियों पर अवैध खनन,

कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई शुरू हुई तो धीरे-धीरे उत्तर भारत में कई तरह के संकट के बादल मंडराने लगेंगे।

1- रेगिस्तान पर नहीं लग पाएगी लगातार : अरावली 'धार रेगिस्तान' को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। इसके नष्ट होने से उत्तर भारत भी रेगिस्तानी हो जाएगा। क्योंकि ये पहाड़ियां आखिरी दीवार हैं, जो इसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। जमीन बंजर होने लगेगी। खेती करना मुश्किल हो जाएगा और धीरे-धीरे सूखा अपनी गिरफ्त में ले लेगा।

2- बेमौसम बारिश और बढ़ेगा सूखे का सिलसिला : अरावली हवा की दिशा को प्रभावित करती है। इससे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश संभव होती है। सूखा और बाढ़ का संतुलन बना रहता है। अगर ये पहाड़ियां नष्ट या कमजोर हुईं तो बेमौसम बरसात और सूखा पड़ेगा। इसका सीधा-सीधा और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और कमजोर किसानों को होगा।

3- अरावली नहीं, तो पानी नहीं? : वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो अरावली की चोटियों प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। ये बारिश का पानी रोकती हैं। धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाती हैं। इससे दिल्ली-NCR, हरियाणा और राजस्थान के

कई इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। अब अगर ये संयोजन पहाड़ियां ही नष्ट होने लगेगी, तो उत्तर भारत को पानी के संकट से कोई नहीं बचा पाएगा।

4- करोड़ों जिनगीयों पर मंडराएगा सांसों पर संकट : दिल्ली की हवा में जो धूल और प्रदूषण आता है, उसका बड़ा हिस्सा पश्चिमी दिशा से आता है। अरावली पहाड़ियां इन धूल भरी आंधियों को रोकती हैं। ये PM10 और प्रदूषक कणों को सीमित करती हैं। अगर अरावली नष्ट हुई, तो AQI और खराब होगा। सांस की बीमारियां बढ़ेंगी। बच्चों और बुजुर्गों का जीवन और कठिन होगा।

5- पेड़-पौधे और जीव जंतु भी खतरे में : आखिरी में बात करें तो अरावली पहाड़ियों पर हजारों-लाखों किस्म के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। यहां सैकड़ों प्रजाति के पौधे, पक्षी, स्तनधारी जीव और कीट-पतंगे रहते हैं। अगर ये पहाड़ियां नुकसान झेलेंगी तो इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या फूड चैन को लेकर आएगी। क्योंकि जंगल कटेंगे, आवास खत्म होंगे तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और फूड चैन का क्रम भंग हो जाएगा। क्योंकि इसान भी इसी फूड चैन का हिस्सा है।

MOTIVATIONAL

पैसा नहीं, सोच बनाती है इंसान को अमीर: सुधा मूर्ति के जीवन से सीखें अनमोल सबक

सुधा मूर्ति का जीवन सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी, विनम्रता और सेवा में छिपी होती है। एक सौशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनके विचार आज के समय में बेहद प्रेरणादायक हैं।



• जालंधर बीज . फीचर

सुधा मूर्ति को भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक समाजसेवी, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है। वह इंफोसिस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी बड़े पद या संपत्ति से नहीं बल्कि उनकी सादगी और मानवीय सोच से बनी है। इतने बड़े उद्योगपति परिवार से जुड़ी होने के बावजूद उन्होंने कभी दिखावे या भौतिक सुख-सुविधाओं को अपनी पहचान नहीं बनाया। उनकी सादगी महज बाहरी नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी साफ झलकती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि इंसान जितना सरल होता है, उतना ही मजबूत और संतुलित रहता है। उनके जीवन के अनुभव आज के समय में हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशहाली चमक-दमक में नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सादे जीवन में छिपी होती है।

सादगी ही असली अमीरी है : सुधा मूर्ति का मानना है कि सादगी इंसान को जमीन से जोड़े रखती है। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े परिवार का हिस्सा होने के बावजूद वह साधारण सूती साड़ियां पहनती हैं और आम लोगों की तरह जीवन जीना पसंद करती हैं। उनके अनुसार, दिखावा इंसान को थका देता है, जबकि सादा जीवन मानसिक शांति देता है।

पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं : उनके जीवन का एक बड़ा सबक यह है कि पैसा केवल सुविधा के लिए होना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने

अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए किया। इंफोसिस फाउंडेशन के तहत उन्होंने गांवों में स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल बनवाए जिससे हजारों जिंदगियां बेहतर हुईं।

जड़ों को कभी ना भूलें : सुधा मूर्ति यह भी सिखाती हैं कि सफलता मिलने के बाद अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वह अक्सर अपने बचपन, संघर्ष और गांव से जुड़े अनुभव साझा करती हैं जिससे यह साफ होता है कि विनम्रता इंसान को बड़ा बनाती है। उनका व्यवहार बताता है कि सम्मान पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है।

विनम्रता सबसे बड़ा गुण है : आज की भागदौड़ और दिखावे से भरी दुनिया में सुधा मूर्ति की सादगी हमें यह याद दिलाती है कि कम में खुश रहना ही असली सुख है। उनका जीवन उदाहरण है कि जब सोच साफ होती है तो जीवन अपने आप सरल और अर्थपूर्ण बन जाता है।

सुधा मूर्ति के अनुसार 'पर्याप्त पैसा' क्या है?

जरूरतें पूरी हों, दिखावा नहीं : पैसा इतना हो कि जरूरतें पूरी हों, ना कि दूसरों को प्रभावित करने का साधन बने।

आत्मसम्मान बना रहे : इंसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी ना हो।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश : पैसा वहीं खर्च हो, जहां जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो।

भविष्य की सुरक्षा : बुढ़ापे या आपातकाल के लिए न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा जरूरी है।

समाज को लौटाने की क्षमता : अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो वही सच्ची समृद्धि है।

जीवन मंत्र : 'सुधा मूर्ति मानती हैं कि पैसा कभी 'पर्याप्त' नहीं लगता, अगर इच्छाओं पर नियंत्रण ना हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ज्यादा कमाने की दौड़ में रस्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति खो देते हैं। उनके अनुसार, खुशहाल जीवन का रहस्य ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सीमित इच्छाओं और संतोष में छिपा है।

वायरल तरीका ट्राई करें, कुकर में फटाफट बन जाएगी ढाबे वाली दाल तड़का!

दाल तो घर में लगभग रोज ही बनती है, लेकिन वही सेम स्वाद कई बार थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। आज हम इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फटाफट आप टेस्टी सी दाल बना लेंगी।



• जालंधर बीज. रेसिपी

दाल चावल एक कंफर्ट फूड है। शायद ही कोई होगा जिसने दाल चावल खाना पसंद ना हो। तड़का लगी हुई दाल हो तो खाने का मजा और भी दोगुना हो जाता है। अब दाल तो घर में लगभग रोज ही बनती है, लेकिन वही सेम स्वाद कई बार थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। फिर एक मन होता है कि ढाबा स्टाइल तड़का दाल बना की जाए। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से फिर वही सिंपल दाल पर आ कर गाड़ी रुक जाती है। लेकिन क्या हो अगर आप ढाबा स्टाइल मिक्स दाल तड़का बना लें, वो भी नॉर्मल से कम समय में? आज हम इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फटाफट आप टेस्टी सी दाल बना लेंगी।

कुकर में एक साथ ढाल दें सारी सामग्री

आमतौर आप आप पहले कुकर में दाल उबालती होंगी, फिर दूसरे पैन या कड़ाही में ढेर सारा प्याज-टमाटर डालकर तड़का लगाती होंगी। इसमें काफी समय भी लग जाता है और दाल वही रोज जैसी लगती है। लेकिन इस तरीके में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां आप कुकर में सभी चीजें एक बार में ही थोड़ा बोरिंग लगने लगती हैं। फिर एक मन होता है कि ढाबा स्टाइल तड़का दाल बना की जाए। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से फिर वही सिंपल दाल पर आ कर गाड़ी रुक जाती है। लेकिन क्या हो अगर आप ढाबा स्टाइल मिक्स दाल तड़का बना लें, वो भी नॉर्मल से कम समय में? आज हम इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फटाफट आप टेस्टी सी दाल बना लेंगी।

आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं

1) सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 100 ग्राम अरहर की दाल (तुर दाल) और बराबर मात्रा में ही मसूर की दाल डालें। साथ में ये काफी टेस्टी लगती हैं और पचाने में भी आसान होती हैं।

2) अब इसी प्रेशर कुकर में आपको दो कट्टी हुई और दो साबुत टमाटर एड करने हैं। दाल का

स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से हरे मटर भी डाल दें।

3) दाल में लगभग एक लीटर पानी एड करें, साथ में हल्दी पाउडर और नमक भी मिलाएं। कुकर का ढक्कन बंद करें और 3 सीटी आने तक दाल को पका लें। अब दाल बनने के बाद टमाटर के छिलके निकालकर फेंक दें।

अब बारी है स्पेशल तड़का लगाने की

दाल बन जाए तो ऊपर से एक स्पेशल तड़का एड करें, इसी से असली स्वाद आता है। एक तड़का पैन लें, उसमें घी या तेल गर्म करें। अब इसमें सूखी लाल मिर्च (साबुत) तड़का लें। इसके बाद गैस बंद करें और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड करें। इससे रंगत बहुत अच्छी आती है। अब इस तड़के को दाल में एड करें।

आपकी ढाबा स्टाइल मिक्सड दाल तड़का तैयार है, बिना किसी झंझट के।

सर्दियों में कितने महीने के बच्चे को कैसे नहलाएं, ठंड से बचाने के लिए बरतें ये सावधानी



PARENTING

जालंधर बीज (फीचर) . सर्दियां शुरू होते ही नवजात शिशु की मांएं अकसर परेशान रहती हैं। यही वजह है कि इस मौसम में घर के बड़े-बुजुर्ग नवजात बच्चे को नहलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह अकसर नई माओं को देते रहते हैं।

सही समय : एक्सपर्ट कहती हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों को नहलाने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होता है। इस दौरान धूप निकलने से वातावरण अपेक्षाकृत गर्म बना रहता है।

कमरे को करें प्रीहीट : बच्चे को नहलाने से 5 से 10 मिनट पहले हीटर या रूम हीटर चलाकर कमरे का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। खिड़की-दरवाजे बंद करें ताकि बच्चे को हवा न लगे।

नहाने के समय का रखें ख्याल : एक्सपर्ट कहती हैं कि बच्चों को ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए। 0 से 1 साल के बच्चे को केवल 5 से 7 मिनट तक ही नहलाएं। 1 से 3 साल के बच्चों को 10 से 12 मिनट से ज्यादा न नहलाएं।

मॉइश्चराइज करना ना भूलें : बच्चे को नहलाने के बाद उसके शरीर को तौलिए से अच्छी तरह पोछकर सुखाने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी त्वचा पर थिक मॉइश्चराइजर लगाएं। इससे उनकी त्वचा में नमी बनी रहने के साथ सर्दियों की शुष्क हवा से बचाव भी होगा।

किस उम्र में कैसे नहलाएं : • नवजात (0-3 महीना) के लिए स्पंज बाथ बेहतर रहती है। • 3 महीने से बड़े बच्चे को टब में नहलाएं।

बरतें ये सावधानियां : • बच्चे को नहलाते समय कभी भी पानी में अकेला न छोड़ें। • अगर बच्चा रो रहा हो या बुखार हो तो न नहलाएं। सिर्फ स्पंज से साफ करें। • बेबी प्रोडक्ट्स हमेशा पैराबीन, सल्फेट फ्री होने के साथ डॉक्टर की सलाह से ही चुनें। • नहलाने के बाद बच्चे को अच्छे से मॉइश्चराइज करें क्योंकि सर्दी में त्वचा रूखी हो जाती है। • अगर बच्चे को ठंड लगाने के लक्षण दिखें (ठंडे हाथ-पैर, छींकें) तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्कलेमर : इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रोल पर आधारित है। जालंधर बीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

सावधान! सांसों में घुलता जहर सिर्फ फेफड़े नहीं, आपकी याददाशत भी सुखा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कैसे

• जालंधर बीज. हेल्थ केयर

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वह न सिर्फ आपके फेफड़ों को काला कर रही है, बल्कि आपकी यादों को भी मिटा रही है? आज किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में सिर्फ 70-80 साल के बुजुर्ग लोग ही नहीं, बल्कि 30 और 40 साल की उम्र के युवा भी याददाशत की कमी (Brain fog) और संज्ञानात्मक गिरावट (Cognitive decline) की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (साकेत) के हेड न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हवा में प्रदूषण लगातार खबरों में बना रहता है, और हम अक्सर ऐसे परिवारों से मिलते हैं जो अपने बुजुर्ग माता-पिता में याददाशत कम होने को लेकर चिंतित रहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या प्रदूषण इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा उनके मन को यह सवाल भी अकसर परेशान करता है कि क्या लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से खुद उनके लिए भी भविष्य में याददाशत कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ते शोध के आधार पर, इसका जवाब तेजी से चिंताजनक होता जा रहा है।

बढ़ते प्रदूषण का फेफड़ों के साथ दिमाग पर भी असर वायु प्रदूषण सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वाहन से निकलने वाले धुएँ और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले सूक्ष्म कण, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है, इतने छोटे होते हैं कि वे हमारे रक्तप्रवाह और यहां तक कि मस्तिष्क ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ये कण डिमेंशिया के जोखिम को काफी बढ़ा देते हैं। PM2.5 में थोड़ी सी भी वृद्धि डिमेंशिया विकसित होने के जोखिम को 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देती है। नाक से होकर सीधे दिमाग में पहुंचते हैं PM2.5 कण



न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने दिमाग को एक सुरक्षित घर की तरह सोचें, जिसमें दरवाजे और पहरेदार होते हैं। अधिकांश खतरों को दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन PM2.5 कण माइक्रोस्कोपिक जासूसों की तरह होते हैं, जो आपकी नाक से होकर घुस जाते हैं और प्राण तंत्रिका प्रदूषण दिमाग में जमे प्लाक्स को साफ करने की क्षमता पर डालता है असर आपके दिमाग की प्रतिरक्षा प्रणाली सुरक्षा गार्डों की तरह काम करती है। सामान्यतः, वे न्यूरोन्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब प्रदूषण के कण दिमाग में प्रवेश करते हैं, तो वे अव्यवस्था और असंतुलन पैदा करते हैं। ये गार्ड कभी-कभी मस्तिष्क कोशिकाओं और उनकी कनेक्शनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। प्रदूषण अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार अमाइलॉइड-बीटा प्लाक्स के जमा होने को भी तेज कर देता है। शोध से पता चलता है कि प्रदूषित हवा दिमाग की इन प्लाक्स

न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अक्सर ऐसे परिवारों से मिलते हैं जो अपने बुजुर्ग माता-पिता में याददाशत कम होने को लेकर चिंतित रहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या प्रदूषण इसका कारण हो सकता है।

को साफ करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे ये तेजी से जमा होने लगती हैं। आनुवंशिक कमजोरी और पर्यावरणीय प्रदूषण का मेल संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट को बढ़ाता है।

हवा साफ होने पर भी बना रहता है खतरा : ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नुकसान तब भी होता है जब प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों से नीचे होता है। हवा साफ दिख सकती है, लेकिन अदृश्य कण खतरा बनाए रखते हैं। अच्छी बात यह है कि यह एक रोकी जा सकने वाली समस्या है।

बचाव के उपाय : आनुवंशिक कारणों के विपरीत जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना हमारे हाथ में है। स्वच्छ परिवहन का समर्थन, औद्योगिक उत्सर्जन पर कड़े नियम, और बेहतर शहरी योजना सीधे तौर पर मस्तिष्क के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। **व्यक्तिगत स्तर पर उठाएँ ये कदम** : व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ सरल कदम मदद कर सकते हैं। घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग, अधिक प्रदूषण वाले दिनों में बाहर व्यायाम से बचना, और भारी ट्रैफिक के दौरान मास्क पहनना जैसे सामूहिक प्रयास वास्तविक बदलाव लाने के लिए आवश्यक हैं।

डिस्कलेमर : यह खबर सामान्य जानकारीयों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 संरचनात्मक कमियों को दूर करता है

• जालंधर बीज . नई दिल्ली

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है और सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और व्यापक वितरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, ताकि ग्रामीण भारत मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके।

सुधारों की गलत व्याख्या : वीबी- जी राम जी अधिनियम लागू होते ही कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, जो गहराई से देखने पर सही नहीं ठहरतीं। कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी कमजोर कर दी गई है, विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को बिना परामर्श के कमजोर किया गया है और यह सुधार असल में राजकोपीय खर्च घटाने का तरीका है, जिसे ढांचे में बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन ये सभी दावे इस कानून के असली उद्देश्य और प्रावधानों को ठीक से न समझ पाने के कारण किए जा रहे हैं।

इस गलतफहमी का मूल कारण एक गहरी वैचारिक त्रुटि है- यह मान लेना कि कल्याण और विकास एक दूसरे के विरोधी विरोधी विकल्प हैं। नया ढांचा इसके बिल्कुल उलट सोच पर आधारित है : कल्याण, जो कि वैधानिक आजीविका गारंटी को मजबूत करने पर केंद्रित है, और विकास, जो कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है, परस्पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आय सहायता, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और लंबे समय की ग्रामीण उत्पादकता

को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि कानूनी संरचना में ही शामिल सोच है।

यह कहना कि कानूनी रोजगार अधिकार कमजोर कर दिया गया है, सही नहीं है। इस कानून में रोजगार गारंटी का वैधानिक और न्यायिक अधिकार बरकरार रखते हुए उसे और मजबूत किया गया है। अधिकार घटाने के बजाय इसे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहले जो प्रक्रियागत शर्तें बेरोजगारी भत्ता मिलने में रुकावट बन जाती थीं, उन्हें हटा दिया गया है और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। यह सुधार लंबे समय से मौजूद उस अंतर को दूर करने का प्रयास है, जो कागज़ पर किए गए वादे और लोगों के धरातल के अनुभव के बीच था।

यह भी कहा जा रहा है कि मांग-आधारित रोजगार छोड़कर ऊपर से थोपे गए योजनागत मॉडल को लागू कर दिया गया है। यह भी एक गलत धारणा है। काम की मांग पहले की तरह ग्रामीण मजदूरों से ही आती है। फर्क यह है कि अब काम तभी शुरू नहीं किया जाएगा जब मजदूरी या संकट बढ़ जाए, बल्कि पहले से ही भागीदारी आधारित ग्राम-स्तरीय योजना बनाकर तैयारी कर ली जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब मजदूर काम मांगें, तो उनके लिए तुरंत काम उपलब्ध हो, और प्रशासनिक तैयारी न होने के कारण उन्हें मना न किया जाए। इस तरह योजना बनाया मांग को दबाना नहीं, बल्कि उसे सही रूप से लागू करता है। केंद्रीकरण का आरोप इस कानून की पूरी संरचना को नज़रअंदाज़ करता है।



शिवराज सिंह चौहान
(केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

ग्राम पंचायतों पहले की तरह ही योजना बनाने और लागू करने की प्रमुख संस्था बनी रहती हैं और ग्राम सभाओं के पास स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार यथावत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब विकेंद्रीकरण बिना व्यवस्था के या कभी-कभार होने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि एक नियमित, व्यवस्थित और सहभागी प्रणाली के रूप में होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, समन्वय और पारदर्शिता हो सके - न कि स्थानीय प्राथमिकताओं को दबाने के लिए। केंद्रित किया गया है सिर्फ व्यवस्था और सामंजस्य को, निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ही रहेगा। इस तरह यह कानून बिखराव को ठीक करता है, विकेंद्रीकरण को कमजोर नहीं करता।

यह आरोप भी सही नहीं है कि इस सुधार को बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया गया। इस विधेयक से पहले

राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, तकनीकी कार्यशालाएँ और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं। गांव-स्तरीय योजना संरचना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय की व्यवस्था और डिजिटल गवर्नंस सिस्टम जैसे प्रमुख प्रावधान राज्यों से मिले सुझावों और वर्षों के अनुभव से सीखे गए सबक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

आवंटन में वृद्धि, समानता : यह धारणा भी तथ्यों से मेल नहीं खाती कि पिछले दशक में रोजगार गारंटी को लगातार कमजोर किया गया। बजट आवंटन 2013-14 के ₹33,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹2,86,000 करोड़ हो गया। 2013-14 तक कुल 1,660 करोड़ मानव-दिवस के बदले अब तक 3,210 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ। केंद्र से जारी धनराशि ₹2.13 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.53 लाख करोड़ हो गई और पूरे हुए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख तक पहुँच गए। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 56.73% हो गई। अब 99% से अधिक फंड ट्रांसफर आदेश समय पर जारी होते हैं और लगभग 99% सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हैं। ये सभी रूढ़ानु उपेक्षा नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर प्रदर्शन को दिखाते हैं।

लेकिन समय के साथ यह भी साफ हो गया कि पुराने ढांचे में खुद कुछ बुनियादी कमजोरियाँ थीं-जैसे बीच-बीच में ही काम मिलना, बेरोजगारी भत्ता लागू करने की कमजोर व्यवस्था, बिखरे हुए और असंगठित तरीके से संपत्ति/संसाधन निर्माण, और अल्पसंख्यक व फर्जी प्रविष्टियों की गुंजाइश। ये कमजोरियाँ सूखे के समय, बड़े पैमाने पर पलायन के दौर में और

कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान जमीन पर साफ दिखाई दीं। नए कानून के तहत की गई वित्तीय व्यवस्था को भी गलत तरीके से सरकारी जिम्मेदारी छोड़ने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सच यह है कि केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है। केंद्र का हिस्सा ₹86,000 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹2,95,000 करोड़ तक हो रहा है, जो ग्रामीण रोजगार के प्रति मजबूत और बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। 60:40 की फंडिंग व्यवस्था वैसे ही है जैसी अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में वर्षों से लागू है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 का अलग अनुपात रखा गया है। इसलिए यह किसी तरह की वित्तीय पीछे हटने का संकेत नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को और मजबूत करने का संकेत है।

न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए धन आवंटन नियमों के आधार पर किया जाता है, और राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए नियमों में दिए गए स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ मानदंडों का पालन किया जाता है। राज्यों को सिर्फ लागू करने वाली एजेंसियों की तरह नहीं, बल्कि विकास के भागीदार के रूप में देखा गया है, जिन्हें कानूनी ढांचे के भीतर अपनी योजना अधिसूचित करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है। लचीलापन भी बरकरार रखा गया है- प्राकृतिक आपदा या विशेष परिस्थितियों में राज्य अतिरिक्त रूप, अधिक प्रकार के कार्य और अस्थायी रूप से रोजगार बढ़ाने जैसी सिफारिशें कर सकते हैं। इस तरह नियम-आधारित आवंटन और परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन, दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सहकारी

संवाद को मजबूत किया गया है।

यह कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे पहले से ही एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि तय कर सकें, जो बुआई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसमों को कवर करे, और उन दिनों के दौरान काम न करया जाए। यह घोषणा ज़िला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर, स्थानीय मौसम और कृषि परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बड़ी हुई रोजगार गारंटी कृषि कार्यों में बाधा न बने, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर चले।

यूपीए का रिकॉर्ड : कांग्रेस नेतृत्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही मनरेगा से जुड़े वादों को अमल में लाने में विफल रही। कांग्रेस के घोषणापत्र में " प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मजदूरी पर कम से कम 100 दिन का काम" देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने 2009 में ही मजदूरी 100 रुपये पर सीमित कर दी और कई सालों तक महंगाई और ग्रामीण संकट की अनदेखी करते हुए इसे इसे बढ़ाया भी नहीं। केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि राज्य सरकारों इस योजना के तहत मनमाने ढंग से काम कर रही थीं और मजदूरी न बढ़ाने का कारण भी राज्यों के 'अनियंत्रित बढ़ोतरी' को बताया। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में शासन की एक गंभीर विफलता दिखाती है: कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी ही राज्य सरकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी, जिसके कारण मनरेगा में दुरुपयोग, फर्जी जाँच कार्ड और वित्तीय गड़बड़ियाँ जैसी समस्याएँ पैदा हो गईं।

सर्दियों को देखते हुए, जम्मू मंडल में ट्रेनों के समय पर संचालन हेतु " स्क्रैच रेक " / अतिरिक्त रेक की व्यवस्था



• जालंधर बीज . जम्मू

उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन में होने वाली देरी को कम करने और यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में " स्क्रैच रेक " / अतिरिक्त रेक की व्यवस्था की गई है, जिसे भारी कोहरे या अन्य समस्याओं के कारण मूल ट्रेन के विलंबित होने की स्थिति में संचालन के लिए तैयार रखा जाता है।

इसी सुविधा के साथ ट्रेन संख्या 12414 (जम्मूतवी-अजमेर) तथा ट्रेन संख्या 22478/ 22477 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा - नई दिल्ली - कटरा) इन ट्रेनों के देरी से चलने व देरी से आने के एवज में " स्क्रैच रेक " / अतिरिक्त रेक की व्यवस्था रखने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक, विवेक कुमार के निर्देशन व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के नेतृत्व में लिया गया है। ताकि सर्दियों के मौसम में कोहरे से लेट हुई, ट्रेनों को समय पर चलाया जा सके। जिससे की यात्री अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुँच सके। इन ट्रेनों

के लेट होने के एवज में " स्क्रैच रेक " / अतिरिक्त रेक एक समाधान हैं। जो ट्रेनों सात घंटे या उससे अधिक देरी व अनिश्चित काल के लिए लेट होती हैं। उस दौरान इन " स्क्रैच रेको " / अतिरिक्त रेको का उपयोग करके, लेट ट्रेनों की समयबद्धता को बनाया जा सकता है। साथ ही यात्रियों को घंटों रेलवे स्टेशन पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा व ट्रेन सही समय पर प्रस्थान करेगी।

जम्मू मंडल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई, पहल पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिंघल ने कहा, " कि यह रेलवे द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य उंड में कोहरों के दौरान यात्रियों को आरामदायक और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित हो सके। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट होती हैं। इन " स्क्रैच रेको " / अतिरिक्त रेको का संचालन यात्रियों के लिए सकारात्मक रहेगा व ट्रेनों के समय पर संचालन में भी सहायक सिद्ध होगा। इस तरह के अतिरिक्त उपायों से भविष्य में भी यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह सफल संचालन रेलवे के कुशल प्रबंधन और यात्रियों की जरूरतों को समझने का प्रमाण है।

AIIMS नई दिल्ली के RDA प्रेसिडेंट ने ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की

• जालंधर बीज . नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के अध्यक्ष डॉ. साई कौस्तुभ ने एक महत्वपूर्ण अकादमिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर की सुपर-स्पेशियलिटी परीक्षा में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट (AML) में द्वितीय रैंक प्राप्त कर सजिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हेपेटो-पैनक्रियाटो-बिलियरी (HPB) एवं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में AIIMS नई दिल्ली में प्रवेश प्राप्त किया है।



डॉ. साई कौस्तुभ की यह उपलब्धि न केवल उनकी असाधारण शैक्षणिक प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि सर्जरी के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ, निरंतर परिश्रम एवं समर्पण का भी प्रमाण है। सजिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर

ट्रांसप्लांट सर्जरी चिकित्सा विज्ञान के सबसे जटिल एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मानी जाती है, जहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. साई कौस्तुभ वर्तमान में AIIMS नई दिल्ली के रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इस भूमिका में उन्होंने रेज़िडेंट डॉक्टर्स से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संस्थान एवं प्रशासन के समक्ष रखा है। उनकी यह सफलता युवा चिकित्सकों के लिए प्रेरणास्रोत

है और यह दर्शाती है कि नेतृत्व क्षमता और अकादमिक उत्कृष्टता साथ-साथ आगे बढ़ सकती हैं। चिकित्सा जगत में डॉ. साई कौस्तुभ की इस उपलब्धि पर सहयोगियों, शिक्षकों एवं शुभचिंतकों द्वारा उन्हें हार्दिक बधाइयाँ दी जा रही हैं।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 10वां स्वच्छ सर्वेक्षण किया लॉन्च

जालंधर बीज (नई दिल्ली) . केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के लिए टूलकिट जारी किया। विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण (एसएस), एक दशक पूरा कर चुका है। एसएस केवल एक वार्षिक सर्वेक्षण नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रबंधन उपकरण है। कचरा मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से यह परिवर्तन को गति प्रदान कर रहा है। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का विषय है: स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएँ हाथ, करें सफाई साथ। नगर आयुक्तों और अन्य राज्य प्रतिनिधियों सहित सभी राज्य और शहरी स्थानीय निकायों ने आभासी माध्यम से

इस शुभारंभ में भाग लिया। शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए, स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता के लिए एक मानक स्थापित किया है। इसने मूल्यांकन मापदंडों के मानकीकरण, स्वच्छ शहर के लिए रोकथाम तैयार करने, स्वच्छ शहर बनाने के चरणों और घटकों को निर्धारित करने और अंततः जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाली स्वच्छता के माध्यम से स्वच्छ शहरों को सक्षम बनाने में मदद की है। पिछले 10 वर्षों में, स्वच्छ सर्वेक्षण सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी का एक उल्लेखनीय उदाहरण रहा है, जो स्वच्छता को जीवन शैली बनाने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है - वास्तव में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता को प्रतिबिंबित करता है।

NEIGRIHMS शिलांग में रोड सेफ्टी सेमिनार; पद्मश्री प्रो. बी. के. एस. संजय ने जताई तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता



• जालंधर बीज . जम्मू

उत्तर-पूर्वी हिंदिरा गांधी स्वास्थ्य और सहयोगी विज्ञान संस्थान (NEIGRIHMS), शिलांग में 22 दिसंबर 2025 को रोड सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पेश करना था। पद्मश्री प्रो. डॉ. बी. के. एस. संजय, अध्यक्ष, एम्स गुवाहाटी ने कहा कि भारत और विशेषकर मेघालय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। लगभग 90 प्रतिशत दुर्घटनाएँ वाहन चालकों की लापरवाही के कारण होती हैं और इन्हें रोकना संभव है। तेज गति और अनुशासनहीन ड्राइविंग मुख्य कारण हैं, जिन्हें जागरूकता, शिक्षा और नियमों के पालन से सुधारा जा सकता है।

प्रो. संजय ने मेघालय की सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत से अधिक बताया और हाल की कई हताहत घटनाओं का हवाला देते हुए तत्काल निवारक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जनता से ट्रेफिक नियमों का पालन करने और जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने का आग्रह किया।



रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट और ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉ. गौरव संजय ने कहा कि हेल्मेट और सीट बेल्ट का उपयोग दुर्घटनाओं में की गई गंभीरता और संख्या दोनों को काफी हद तक कम कर सकता है।

प्रो. संजय ने NEIGRIHMS प्रशासन, विशेषकर ऑर्थोपीडिक्स विभाग के प्रमुख प्रो. भास्कर बोरगोहेन का धन्यवाद किया और रोड सेफ्टी पर विचार साझा करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया।

भारत के नए मुक्त व्यापार समझौते से खेत से लेकर कारखाने तक रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी

• जालंधर बीज . नई दिल्ली

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम को प्रतिबिंबित करता है - यह रोजगार सृजन को तेज करता है, निवेश को बढ़ावा देता है और भारत के छोटे व्यवसायों, छात्रों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए परिवर्तनकारी अवसरों के द्वार खोलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित यह समझौता, मोदी सरकार किया गया सातवां एफटीए है और 2025 का तीसरा प्रमुख व्यापार समझौता है, जो ब्रिटेन और ओमान के साथ हुए ऐतिहासिक, लाभकारी समझौतों के बाद हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी एफटीए विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से काफी अधिक है। यह एफटीए वैश्विक व्यापार वार्ताओं में भारत की बढ़ती शक्ति और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

प्रत्येक समझौते पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद वार्ता की गई है, जिससे संतुलित परिणाम सामने आये हैं और विकसित दुनिया के साथ वास्तविक लाभकारी सहभागिता सुनिश्चित हुई है। रोजगार, विचार और बाजार पहुंच इस एफटीए का एक केंद्रीय स्तंभ रोजगार सृजन है। न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात की

शत-प्रतिशत पहुंच के लिए शून्य-शुल्क की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भारत के श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, परिधान, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प और ईजीनिरियरि वस्तुओं को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ भारतीय श्रमिकों, कारीगरों, महिला उद्यमियों, युवाओं और एम्एसएमई क्षेत्र को मिलेगा। भारत ने अपनी बाजार पहुंच और सेवाओं की पेशकश को भी सुरक्षित किया है, जिसमें दूरसंचार, निर्माण, आईटी, वित्तीय सेवाएँ, यात्रा और पर्यटन समेत 118 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह विस्तारित पहुंच, भारतीय पेशेवरों और व्यवसायों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

पेशेवरों, छात्रों और युवाओं के लिए अवसर इस समझौते में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए प्रवेश और रहने के बेहतर प्रावधान हैं। यह समझौता अध्ययन के दौरान काम करने के अवसर, अध्ययन के बाद रोजगार और एक सुव्यवस्थित कार्य-अवकाश (वर्किंग-हॉलिडे) वीजा व्यवस्था को सक्षम बनाता है। एफटीईएम स्नातक और परामर्शदाता अब तीन वर्षों तक काम कर सकते हैं, जबकि डॉक्टरेट शोधकर्ता चार वर्षों तक काम कर सकते हैं, जिससे भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व वैश्विक अनुभव और कैरियर के मार्ग खुलते हैं। एक नया अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा उन कुशल भारतीय पेशेवरों का



पीयूष गोयल
(लेबर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं)

समर्थन करता है, जो अंतरराष्ट्रीय अवसरों की तलाश में हैं। किसानों की तरक्की प्रधानमंत्री मोदी का विज्ञान स्पष्ट है: भारतीय किसानों को वैश्विक मंच पर सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। एफटीए इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस समझौते के तहत सेब, कीवी और शहद को शामिल करते हुए एक कृषि उत्पादन साझेदारी स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। न्यूजीलैंड ने बासमती चावल के लिए जीआई स्तर सुरक्षा देने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारतीय चावल किसानों को मजबूत समर्थन मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से, भारत ने सुनिश्चित किया है कि चावल, डेयरी, गेहूँ,

सोया और अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें और किसी भी बाज़ार के खुलने से घरेलू आजीविका को कोई नुकसान ना पहुँचे।

अभिनव एफटीए और निवेश प्रतिबद्धताएं भारत के एफटीए आज सिर्फ शुल्क-कटौती से कहीं आगे बढ़ गये हैं। ये एफटीए किसान, एम्एसएमई, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर खोलने के उपाय हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी करते हैं।

विभिन्न व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यात तत्काल या तेज शिल्क उन्मूलन के जरिये लाभान्वित होता है, जबकि भारत के अपने बाजार का खुलना सोच-समझकर और धीरे-धीरे हो रहा है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत के ईएफटीए देशों - स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेंस्टाइन - के साथ हुए एफटीए के निवेश से जुड़े अभिनव प्रावधानों को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड के लिए, यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक बड़े छलांग का प्रतीक है। पिछले 25 वर्षों में, न्यूजीलैंड ने भारत में लगभग 643 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नई प्रतिबद्धता - अगले 15 वर्षों में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये - एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें निवेश लक्ष्यों को पूरा न करने पर दुबारा पूरा करने की व्यवस्था का प्रावधान है। इस

निवेश का अधिकंश हिस्सा कृषि, डेयरी, एमएसएमई, शिक्षा, खेल और युवाओं के विकास का समर्थन करेगा, जिससे व्यापक और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए यह समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है: यह भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए है। वार्ता करने वाली पूरी टीम के सदस्यों में - मुल्लू वार्ताकार और उपमुख्य वार्ताकार से लेकर वस्तु, सेवा, निवेश की प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में हमारी राजदूत तक - अधिकंश महिलायें थीं। हमारी संक्षम महिलाएं प्रधानमंत्री के विकास एजेंडा में नेतृत्व भूमिका निभाने लगी हैं। भारत की एफटीए रणनीति भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत की स्पष्ट रणनीति का उदाहरण है: विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी करना, जो भारतीय उत्पादों के साथ अर्जुचित प्रतिस्पर्धा किए बिना भारत के श्रम-प्रधान समझौते मात्र लेन-देन नहीं हैं-ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारतीयों, विशेषकर सबसे गरीब लोगों, के जीवन को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं। इस रणनीति ने भारत के 2014 के 'कमजोर पांच' में एक होने की स्थिति को बदल दिया है, अब देश वैश्विक विकास का इंजन और वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश का पसंदीदा साझेदार

बन गया है। आज भारत आत्मविश्वास और ताकत के साथ वार्ता करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कृषि, डेयरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहें और समझौते लाभ तभी किए जाएं, जब वे पारस्परिक काल प्रदान करते हैं। व्यापार शासन में ताजगी भरा बदलाव भारत का वर्तमान दृष्टिकोण अतीत की तुलना में बहुत अलग है। पहले की व्यापारिक नीतियाँ अक्सर पर्याप्त परामर्श के बिना, भारतीय बाजारों को सस्ते आयात के जोखिम में डाल देती थीं तथा छोटे व्यवसायों और नौकरियों को खतरे में डालती थीं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और वार्ता शक्ति को बहाल किया है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिसे भारतीय उद्योग जगत में सराहना मिली है, 2014 के बाद शासन में हुए इस ताजगी भरे बदलाव का परिणाम है। वस्तु, सेवा, निवेश और गतिशीलता को एकीकृत करके और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए, यह समझौता भारत की आधुनिक, समावेशी और संतुलित व्यापार कूटनीति को प्रतिबिंबित करता है। जैसे-जैसे भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक एकीकरण को मजबूत कर रहे हैं, यह एफटीए दिखाता है कि व्यापार कैसे बाजार को खोल सकता है और सीमाओं के पार मानव-केंद्रित विकास और साझा समृद्धि प्रदान कर सकता है।

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 299वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 115 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़ (जालंधर बीज). मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खाले के लिए शुरू की गई नशों के खिलाफ मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को लगातार 299वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 285 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पूरे राज्य में 87 एफआईआर दर्ज कर 115 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 299 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 41,775 हो गई है।

इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 268 ग्राम हेरोइन, 1,860 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल तथा 6,700 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है। इस अभियान के दौरान 61 गजटेट अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 285 स्थानों पर छापेमारी की। दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 276 संदिग्ध व्यक्तियों को भी जांच की।

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्टल बरामद



• जालंधर बीज. जालंधर

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे खास अभियान के तहत लूट में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 02 गैर-कानूनी पिस्टल बरामद करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि यह कार्रवाई ईचार्ज सीआईए-स्टाफ जालंधर और एसएचओ पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 8 जालंधर की पुलिस टीमों ने मनप्रीत सिंह दिल्ली, डीसीपी/आईएनवी, जयंत पुरी, एडीसीपी/आईएनवी, आर्कषि जैन, एडीसीपी-1, संजय कुमार, एसीपी/नाथ और



अमरबीर सिंह, एसीपी/डी की देखरेख में की। उन्होंने बताया कि 22.12.2025 की रात को पुलिस को सूचना मिली कि दो अनजान लोगों ने बंदूक को नोक पर एक गाड़ी लट्टने की कोशिश की है। इस बारे में, जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 में संवधान 302(2), 3(5), 62 बीएनएस और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत केस नंबर 311 तारीख 23.12.2025 को दर्ज किया गया था। केस की जांच के दौरान, पुलिस टीम ने टेक्निकल मदद और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करके, रमणीक एवेन्यू से बुलंदपुर रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी



कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशदीप सिंह उर्फ अरॉ, बेटा कश्मीर सिंह, गांव नवा नौशेरा, थाना पुराना शाला, जिला गुरदासपुर और तेजबीर सिंह उर्फ तेजी, बेटा सुखविंदर सिंह, गांव कोट बुड्ढा, थाना सेखवा, जिला बटाला के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 01 पिस्टल 32 बोर और 01 पिस्टल 30 बोर बरामद की है। कमिश्नरेट पुलिस जालंधर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और गैर-कानूनी कार्यों में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एमएसएमई मंत्रालय ने जालंधर में खेल श्री अकाल तख्त सबसे ऊपर : बलतेज पन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र को दी मंजूरी

• जालंधर बीज. चंडीगढ़

पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन तथा एनआरआई मामलों के माननीय कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने 21 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री जितन राम मांझी से भेंट कर पंजाब के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल सहयोग का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से जालंधर में केंद्रित खेल सामग्री उद्योग पर जोर दिया।

बैठक के दौरान संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब का खेल सामग्री उद्योग निर्यात की अपार संभावनाओं से युक्त है, किंतु इसे प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विकास, परीक्षण सुविधाओं तथा वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जालंधर में प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (पीपीडीसी), मेरठ के अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर (टीईसी) की स्थापना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अवसरचना उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पिछले आठ महीनों से मंत्रालय में लंबित था।



इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2025 को प्रधान निदेशक आदित्य प्रकाश शर्मा के माध्यम से एक आधिकारिक पत्र जारी किया, जिसमें जालंधर स्थित सरकारी चमड़ा एवं फुटवियर प्रौद्योगिकी संस्थान (जीआईएलएफटी) में स्वीकृत टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर तथा लीज डीड के निष्पादन का आह्वान किया गया।

यह स्वीकृति हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसमें टीईसी को पीपीडीसी, मेरठ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर 5 जनवरी, 2026 को जालंधर में हस्ताक्षर किए जाने प्रस्तावित हैं।

पत्र के अनुसार, जीआईएलएफटी

भवन के ग्राउंड, प्रथम एवं द्वितीय तल पर स्थित कुल 11,166 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र को इस केंद्र की स्थापना हेतु पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। यह टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर उन्नत उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परीक्षण सुविधा, कौशल विकास तथा परामर्श एवं हैंडहोल्डिंग सहायता जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे विशेष रूप से खेल सामग्री एवं संबंधित विनिर्माण इकाइयों को लाभ मिलेगा।

इस निर्णय का स्वागत करते हुए संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री का समर्पणित हस्तक्षेप के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर पंजाब के खेल सामग्री उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर सिद्ध होगा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा और निर्यात को नया प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र के शीघ्र संचालन हेतु पंजाब सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

यह पहले केंद्र-राज्य के मजबूत समन्वय को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को सशक्त बनाना, नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना तथा पंजाब को प्रमुख विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में और अधिक सुदृढ़ करना है।

कहा- 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के गंभीर मामले पर जवाबदेही से भाग रहे धामी

• जालंधर बीज. चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्ना ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 'क्या सरकार खुद को श्री अकाल तख्त से ऊपर समझने लगे गयी है' पर तीखा पलटवार किया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पन्ना ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कभी भी खुद को श्री अकाल तख्त से ऊपर नहीं माना और न ही ऐसी कोई मंशा है, क्योंकि हमारे लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है। एसजीपीसी प्रधान धामी को आड़े हाथों लेते हुए पन्ना ने सवाल किया कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के गंभीर मामले पर सवाल उठाने हैं, तो धामी साहब शोर मचाया क्यों शुरू कर देता है? क्या अपनी जवाबदेही से भागने के लिए आप खुद को



गुरु साहिब से भी ऊपर समझने लगे हैं?

पन्ना ने कहा कि 328 पावन स्वरूपों का मामला सिख संगत की भावनाओं से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। जब भी इस मामले में न्याय या स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, तो धामी साहब इसे 'सरकार का हस्तक्षेप' बताकर असली मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। पन्ना ने धामी के उस हालिया बयान पर भी हैरानी जताई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घपले होते रहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि धामी साहब संगत को बताएं कि ये किस तरह के घपले हैं? क्या ये पैसे की हेराफेरी है, रसीदों का फर्जीवाड़ा है या छापों के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार का हिस्सा है? उनका यह बयान बेहद गंभीर है और दर्शाता है कि संस्था के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं।

वीर बाल दिवस के नाम पर अकाली दल के दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश, पन्ना ने हरसिमरत बादल के पिछले समर्थन पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्ना ने 'वीर बाल दिवस' के नाम को लेकर चल रहे विवाद और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी द्वारा एसजीपीसी में रोजाना हो रहे घोटालों के बारे में दिए गए ताजा बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीर बाल दिवस पर बोलते हुए पन्ना ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जय्यदार ने सांसदों को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की थी, जिसके बाद 'आप' के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और मीडिया के जरिए भी इसे उजागर किया। उन्होंने दोहराया कि 'आप' साहिबजादों को 'बाल' (बच्चे) नहीं मानती बल्कि उन्हें 'बाबाओं' के रूप में सम्मान देती है और उन्हें 'निक्कीआं जिंदों, वहुं साके' का रूप में याद करती है।

पन्ना ने इशारा किया कि जहां शिरोमणि अकाली दल (बादल) आज वीर बाल दिवस के नाम का कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट बताते हैं कि जब वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई थी, तब कई सांसदों ने इसके समर्थन में दस्तखत किए थे, जिनमें सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना और बाद में उससे पीछे हटना अकाली दल का पुराना पैटर्न रहा है, चाहे वो पंथक मुद्दे हों या पंजाब के हित। एक और उदाहरण देते हुए पन्ना ने कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान अकाली नेताओं की भूमिका को याद करते हुए कहा कि किसी ने भी अकाली दल से ज्यादा आक्रामक तरीके से तीन कृषि कानूनों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तब प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल के वीडियो लगातार वायरल किए जाते थे, जिनमें इन कानूनों को फायदेमंद बताया गया था। जब जनता के दबाव में कानून वापस लिए गए तो अकाली नेतृत्व ने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि यह दावा किया कि वे लोगों को कानून 'समझा' नहीं सके।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सैमिनार आयोजित

• जालंधर बीज. जालंधर

जिला कंट्रोलर खाद्य, सिविल सप्लाइज तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सैमिनार आयोजित किया गया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यहां सक्रिट हाउस में आयोजित सैमिनार में कंस्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रधान वरिंदर कुमार, प्रदेश चैयरपर्सन प्रवीण शर्मा, जिला प्रधान हरमीत सिंह मक्कड़, डिपो होल्डर एसोसिएशन, गैस एजेंसी एसोसिएशन तथा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

सैमिनार के दौरान जिला खाद्य एवं सिविल सप्लाइज कंट्रोलर निरंदर सिंह ने उपस्थित लोगों को उपभोक्ता दिवस की शुरुआत, उद्देश्य तथा महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न रूपों



के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। सैमिनार के दौरान विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए कहा गया कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का मूल अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, मानकयुक्त तथा सुरक्षित वस्तुओं की ही बिक्री की जाए। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग से प्रभुजोत कौर, माप-तौल विभाग से अनूप चौधरी तथा डी.एफ.एस.ओ. मुनीश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

फंड घटाकर और अधिकार छीनकर मनरेगा को खोखला किया जा रहा : डॉ. रवजोत सिंह

होशियारपुर (जालंधर बीज). स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलना केवल एक बहाना है, असली मंशा इसके भीतर ऐसे बदलाव करना है जिनसे गरीब और मेहनतकश वर्ग को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90 प्रतिशत फंडिंग करती थी, जिसे अब घटाकर 60:40 कर दिया गया है। वहीं राज्यों का आरडीएफ और जीएफटी का पैसा भी रोका जा रहा है, जो सीधे-सीधे राज्यों के अधिकारों पर हमला है। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि अब केंद्र सरकार यह भी तय करेगी कि गांवों में कौन-सा काम होगा और कौन-सा नहीं। पाइपलाइन, मंडी, निर्माण कार्य या अन्य विकास कार्यों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गांवों के तालाबों की सफाई पांच साल में केवल एक बार करने की शर्त लगाकर पूछा जाना चाहिए कि फिर 125 दिन का रोजगार आखिर कैसे दिया जाएगा। यह गरीबों के मुंह से निवाला छीनने जैसा है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा और इसे विधानसभा में भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले 10 प्रतिशत हिस्सा देती थी, अब 40 प्रतिशत देना पड़ रहा है, जबकि काम का नियंत्रण पूरी तरह केंद्र के हाथ में है।



मोहिंदर भगत ने खोजेवाला चर्च में क्रिसमस संबंधी आयोजित समारोह में की शिरकत

लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए त्याग के मार्ग पर चलने का आह्वान

• जालंधर बीज. कपूरथला

पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी तथा बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा आज क्रिसमस के शुभ अवसर पर खोजेवाला स्थित चर्च में शिरकत की गई और ईसाई भाईचारे के साथ इस पवित्र अवसर की खुशी साझा की गई तथा पूरे प्रदेशवासियों को क्रिसमस के शुभ अवसर की बधाई दी गई। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानवता को जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं फिर भी सत्य पर पूर्ण दृढ़ता और लगन के साथ चलने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्योहार हमें आपसी प्रेम, सद्भावना, दया तथा दूसरों को माफ करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त लोकाई को दिया गया शांति और मानवता का संदेश सभी को हमेशा मानवता की भलाई के लिए प्रयत्न करते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। श्री भगत ने कहा कि ऐसे अवसर न केवल भाईचारे की साझा को मजबूत करते हैं बल्कि समाज को मानवता की सेवा भावना के प्रति प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर आपसी भाईचारा, साझा तथा एक-दूसरे के हमदर्द बनने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें आज ऐतिहासिक मिशन कंफाउंड चर्च, जो कि लगभग 140 साल पुराना है, में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने चर्च की देखभाल के लिए कमेटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। श्री भगत ने इस अवसर पर चर्च ऑफ साईंस एंड वंडर्स द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की।



क्रिसमस का त्योहार हमें आपसी प्रेम, सद्भावना, दया और शांति का देता है संदेश : मोहिंदर भगत

जालंधर (जालंधर बीज). पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी तथा रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज क्रिसमस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यहां मिशन कंफाउंड चर्च तथा चर्च ऑफ साईंस एंड वंडर्स, गांव खांबड़ा में क्रिसमस के शुभ अवसर पर आयोजित समारोहों में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार हमें आपसी प्रेम, सद्भावना, दया तथा दूसरों को माफ करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त लोकाई को दिया गया शांति और मानवता का संदेश सभी को हमेशा मानवता की भलाई के लिए प्रयत्न करते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। श्री भगत ने कहा कि ऐसे अवसर न केवल भाईचारे की साझा को मजबूत करते हैं बल्कि समाज को मानवता की सेवा भावना के प्रति प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर आपसी भाईचारा, साझा तथा एक-दूसरे के हमदर्द बनने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें आज ऐतिहासिक मिशन कंफाउंड चर्च, जो कि लगभग 140 साल पुराना है, में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने चर्च की देखभाल के लिए कमेटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। श्री भगत ने इस अवसर पर चर्च ऑफ साईंस एंड वंडर्स द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की।



तिलक वर्मा ने तीसरे स्थान पर लगाई छलांग

आईसीसी पुरुष टी20 सीरीज : अहमदाबाद में खेले गए निर्णायक मैच में हुई रनों की

स्पोर्ट्स डेस्क. भारत के उभरते हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष टी20 सीरीज में तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। आईसीसी के अनुसार, हाल ही में समाप्त हुई भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पुरुष टी20 प्लेयर रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। इस सीरीज में भारत ने 3-1 से जीत हासिल की।

अहमदाबाद में खेले गए निर्णायक मैच में रनों की बारिश हुई जिसमें मेजबान टीम ने पहली पारी में 231 रन बनाए। भारत के शीर्ष स्कोरर तिलक वर्मा ने 42 रनों में 73 रन बनाए, जिससे उन्हें श्रीलंका के पशुम निस्संका को पीछे छोड़कर 805 रेटिंग अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल करने में मदद मिली, जबकि देवाल्ड ब्रेविस की त्रजे 31 रनों की पारी

ने उन्हें 10वें स्थान पर पहुंचा दिया। तिलक ने चार पारियों में 62.33 के औसत, 131.69 के स्ट्राइक रेट और दो अर्धशतकों के साथ 187 रन बनाकर श्रृंखला में शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना सफर समाप्त किया। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73 रन था।

जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी (चार ओवर में 2/17) की बदौलत भारत लक्ष्य का बचाव करने में सफल रहा। बुमराह मैच के एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनकी इकॉनमी एक रन प्रति गेंद से कम रही। वरुण चक्रवर्ती के चार विकेटों ने रैंकिंग में उनका शीर्ष स्थान और मजबूत कर दिया है। उनकी 804 की रेटिंग दूसरे स्थान पर मौजूद जैकब डफ्री (699) से काफी आगे है। वरुण ने सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता। उन्होंने 11.20 की औसत से 10 विकेट लिए जिनमें एक चार विकेट का कारनामा भी शामिल है।



फोटो-बीसीसीआई